कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी की लगभग 21 प्रतिशत आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68 प्रतिशत आबादी कोल जनजाति की है और यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्‌गम स्थल रीवा जिले के फरेन्दा गांव, कुराली गांव में है। यह कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के पांच गांवों का सैम्पल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य सतना जिले में जो शिक्षा का प्रतिशत है, वह लगभग 32 प्रतिशत है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है, उस 22 लाख में से कोल जनजाति 2.68 लाख है, और इस 2.68 लाख के बीच में चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं, कुछ लोगों ने ही 12वीं की कक्षा पास की हुई है। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं, इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इस कोल जनजाति की जो समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब्स के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब्स के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, वह दूर हो सके और वे विकास की मुख्य धारा में सम्मलित हो सकें तथा उनका भी उत्थान हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Ajay Pratap Singh: Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Santanu Sen (West Bengal) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Now Shri Iranna Kadadi, "Need for Amendment in MPLADS guidelines." Shri Iranna Kadadi; not present. Then, Shri Muzibulla Khan, "Demand to Increase the supply of fertilizers to Odisha."

Demand to increase the supply of Fertilizers to Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, ओडिशा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ओडिशा में जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, उसको फुलफिल किया जाए।

सर, अगर नेशनल लेवल का एवरेज देखा जाए, तो प्रति हैक्टेयर एक क्विंटल 37 केजी के हिसाब से खर्चा होता है या केन्द्र सरकार देती है, लेकिन ओडिशा में 66 किलो ही फर्टिलाइजर

दिया जाता है, इसका मतलब है कि करीब-करीब फिफ्टी परसेंट कम फर्टिलाइजर दिया जाता है। सर, इसीलिए हमारी डिमांड है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ओडिशा में एग्रीकल्चर सैक्टर में 76 परसेंट लोग इन्वॉल्व्ड हैं। 87 लाख, 46 हज़ार हैक्टेयर में फसलें होती हैं, उसमें से 18 लाख, 79 हज़ार हैक्टेयर इरिगेटिड लैंड है। महोदय, इतनी डिमांड करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो रही है और केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है, यह भी मुझे पता नहीं है - मैं इस बात को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं।

उपसभापति जी, हमारे ओडिशा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छी फसल उगा रहे हैं। इसी के कारण केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि कर्मण अवार्ड दिया जाता है, वह ओडिशा सरकार को पाँच बार से ज्यादा बार दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि ओडिशा के किसान बहुत ही अच्छी फसल उगा रहे हैं।

सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता था। छोटे-छोटे बच्चों के पेट में अनाज डालने के लिए उनके परिवार में जो पिता होता था या जो बड़ा होता था, वह चोरी करके अपने बच्चों को अनाज लाकर देता था। खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इस डर से बहुत से किसान रात को खेत में जाकर सोते थे, खेत में रात भर जगते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोई खेत में सोता नहीं है, कोई खेत में जागता नहीं है, क्योंकि सभी के घर में अनाज है। महोदय, इसका मुख्य कारण है कि ओडिशा की सरकार, ओडिशा के मुख्य मंत्री ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, वह उनको लाभ दे रही है और किसान बहुत सुविधा के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर पा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है, जिसका नाम 'कालिया योजना' है। इस योजना के तहत किसानों को 5 हज़ार रुपये सालाना दिए जाते हैं और 50 हज़ार रुपये तक बिना इंटरेस्ट से लोन दिया जाता है। इसी के कारण आज ओडिशा में किसान खुशहाल हैं। यह जो फर्टिलाज़र की शॉर्टेज हो रही है, इसका फुलफिलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ओडिशा के किसानों के लिए फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज की समस्या को दूर किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Muzibulla Khan: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala) and Dr. Santanu Sen (West Bengal).

Dr. Sumer Singh Solanki -- 'Concern over rising cases of online banking fraud in the country'.

Rising cases of online banking fraud in the country

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नर्मदे हर।